**350** वर्षों में ब्रिटिश संसद में ब्रेक्जिट पर सबसे लंबी बहस (तीन सौ दिन की बैठक) चली है। 1642-51 के इंग्लिश सिविल वार के बाद से यह सबसे लंबी बहस है। हाउस ऑफ कामंस ने यह जानकारी दी है।

## संकट की स्थिति में ईरान की उम्मीद भारत और चीन

**संकट की घड़ी में ईरान चीन और भारत की तरफ देखता है, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत आसान नहीं है। अगर भारत अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान से तेल खरीदता है तो भारत पर अमेरिका कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। वहीं चीन के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने पहले से ही ट्रेड वॉर छेड़ रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान से सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाले चीन और भारत क्या उसका साथ देंगे?**

### भारत की मुश्किल

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अभी अमरीका के खिलाफ नहीं जा सकता है। हाल ही में अमरीका ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के संस्थापक **मसूद अजहर** को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में खुलकर मदद की है। ईरानी तेल का भारत, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीददार है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने इसमें कटौती कर दी थी और हर महीने 1.25 मिलियन टन की सीमा तय कर दी थी। 2017-18 में भारत ईरान से प्रतिवर्ष 22.6 मिलियन टन तेल खरीद रहा था। हालांकि भारत का कहना है कि वह ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए सभी संभव तरीकों को खोजने के लिए अमेरिका सहित भागीदार देशों के साथ काम करना जारी रखेगा।

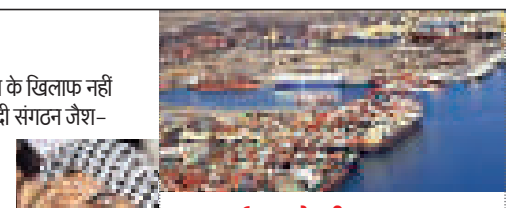

### भारत-ईरान दोस्ती

भारत और ईरान के बीच दोस्ती के मुख्य रूप से दो आधार बताए जाते हैं। एक भारत की ऊर्जा जरूरतें हैं और दूसरा ईरान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा शिया मुसलमानों का भारत में होना। यही नहीं दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की एक वजह चाबाहार पोर्ट भी है। भारत के लिए यह पोर्ट चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती की काट के रूप में देखा जा रहा है।

### चीन पर असर

ईरान पर अमेरिका के नए प्रतिबंधों की वजह से चीन के निजी सेक्टर प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को केवल चीनी निवेश, निर्यात और तेल की खरीदारी से ही मदद मिल सकती है।

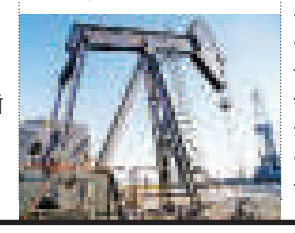

### खराब होती ईरान की स्थिति

अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ईरान में लगातार बदतर स्थिति होती जा रही है। ईरान की मुद्रा रियाल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अनाधिकारिक बाजार में तो एक डॉलर के बदले एक लाख से ज्यादा रियाल देने पड़ रहे हैं। इस साल की शुरुआत में रियाल की कीमत डॉलर की तुलना में मौजूदा वक्त से आधी से भी कम थी। ईरान के पक्ष में कुछ भी सकारात्मक होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब को तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है और सऊदी तैयार भी हो गया है। ईरान के पास विदेशी मुद्रा हासिल करने का कोई जरिया नहीं रहेगा क्योंकि वह तेल का भी निर्यात नहीं करने की स्थिति में होगा। अमेरिका भारत सहित दुनिया के तमाम तेल आयातक देशों पर ईरान से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा है।

## न्यूज गैलरी

### उत्तर कोरिया ने मालवाहक जहाज छोड़ने की मांग की

**सियोल :** उत्तर कोरिया ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर लगे प्रतिबंधों को तोड़ने के मामले में अमेरिका द्वारा पकड़े गए अपने मालवाहक जहाज को तुरंत छोड़ने की मांग की है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका की यह हरकत दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पिछले साल हुए समझौते का उल्लंघन है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, 'इस कार्रवाई से साफ है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर उत्तर कोरिया को घुटनों पर लाना चाहता है। अमेरिका को अपने इस घोर अपराध के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब हम अमेरिका की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे।' अमेरिका के न्याय विभाग ने पिछले सप्ताह कहा था कि यूएन प्रतिबंधों के उल्लंघन पर उत्तर कोरिया के मालवाहक जहाज जब्त कर लिया गया है। (आइएएनएस)

### पाक के कबायली क्षेत्र से होगा अधिक प्रतिनिधित्व

**इस्लामाबाद :** पाकिस्तानी संसद ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है जिससे अब नेशनल असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा (केपी) असेंबली में कबायली इलाकों के लिए सीटों की संख्या में बढ़ोतरी को औपचारिक हरी झंडी मिल गई। 26वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को नेशनल असेंबली में निर्दलीय सांसद मोहसिन डावर ने गुरुवार को पेश किया था। यह विधेयक 342 सदस्यीय सदन में 278 मतों से पारित हो गया। विधेयक के पारित होने के साथ ही पूर्ववर्ती संघीय शासित कबायली इलाके (एफएटीए) के जिलों से नेशनल असेंबली में अब नौ सीटें होंगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इनका प्रतिनिधित्व बढ़कर 26 हो जाएगा। 2018 में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एफएटीए में विलय के बाद नेशनल असेंबली में कबायली जिलों से प्रतिनिधियों की संख्या छह और केपी असेंबली में 16 थी। एफएटीए में विलय के बाद अफगानिस्तान की सीमा से लगते सात कबायली जिलों का अर्ध-स्वायत्त दर्जा खत्म हो गया। विधेयक में महिलाओं के लिए चार सीटें और अल्पसंख्यकों के लिए एक सीट आरक्षित करने का भी प्रावधान है। (प्रेट्र)

### ईरान में जासूसी मामले में एक को जेल भेजा गया

**तेहरान :** अपने देश के खिलाफ जासूसी करने के मामले में ईरान ने अपने एक नागरिक को जेल भेज दिया है। ब्रिटेन के लिए मुखबिरी करने के आरोप में महिला जासूस को पिछले साल पकड़ा गया था। सरकारी मीडिया में सोमवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम करने वाली अरास आमिरी ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया है। ईरान की न्यायपालिका के प्रवक्ता गुलामहुसैन इस्माइली ने सजा की पुष्टि की है। (आइएएनएस)

### नेतन्याहू को सरकार बनाने को मिला और समय

**यरुशलम :** इजरायल में नई सरकार बनाने को मिले 28 दिन खत्म हो जाने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दो सप्ताह का और वक्त दिया गया है। 120 सीटों वाली संसद के लिए बीते नौ अप्रैल को हुए चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी को सबसे ज्यादा 35 सीटें मिली थीं। बहुमत के लिए गठबंधन की कोशिश में लगे नेतन्याहू ने राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन से और समय दिए जाने का अनुरोध किया था। (एपी)

**गहराता संकट** ▶ अमेरिकी रक्षा मंत्री पैट्रिक शानहन ने तेहरान के खिलाफ पेश किया सैन्य प्लान

# ईरान से युद्ध का अमेरिकी खाका तैयार

### पश्चिम एशिया में तनाव के बीच एक लाख 20 हजार सैनिक भेजने की योजना

**द न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन :** ईरान के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर अमेरिका ने युद्ध का खाका तैयार कर लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोगियों के साथ हुई एक बैठक में अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री पैट्रिक शानहन ने अपडेट सैन्य प्लान पेश किया। इसमें पश्चिमी एशिया में एक लाख 20 हजार सैनिकों को भेजने की बात कही गई है।

रक्षा मंत्री ने गत गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को अपने इस प्लान की जानकारी दी। इनमें से कुछ अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार को बताया कि यह सैन्य समीक्षा ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन आर बोल्टन के आदेश पर की गई थी। ईरान को लेकर उनका नजरिया काफी सख्त है। नई योजना में हालांकि थल हमले की बात नहीं की गई है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इस बात को लेकर बेहद अनिश्चितता है कि अफगानिस्तान और सीरिया से अमेरिकी बलों की वापसी की मांग करने वाले ट्रंप वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक पश्चिम एशिया में फिर भेजेंगे।

**ट्रंप प्रशासन में मतभेद :** ट्रंप प्रशासन में ईरान मामले को लेकर मतभेद भी उभरे हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है हि योजना अभी प्रारंभिक अवस्था में है जबकि ईरान से गंभीर खतरा है। वहीं कुछ अन्य अधिकारियों ने ईरान मामले का कूटनीतिक समाधान निकालने का आग्रह किया है।

**इराक की तर्ज पर हमले की आहट :** बैठक में जब एक लाख 20 हजार सैनिकों को भेजने का खाका पेश किया गया तो कई अधिकारी हैरान रह गए। अमेरिका ने जब 2003 में इराक पर हमला किया था तब एक लाख 30 हजार सैनिक मोर्चे पर भेजे गए थे।

**विमानवाहक पोत और बमवर्षक भी तैनात :** ईरान पर दबाव बनाने के लिए पश्चिम एशिया में अमेरिका ने पहले ही एक विमानवाहक पोत और बमवर्षक विमान तैनात कर दिए हैं। पैट्रियॉट मिसाइलों के अलावा कई अन्य युद्धपोतों की भी तैनाती की गई है।

**यूरोपीय देशों ने जताई चिंता :** सहयोगी यूरोपीय देशों के राजनयिकों ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो से मुलाकात की और कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से वे चिंतित हैं।

**अमेरिका के परमाणु करार से हटने से बढ़ा तनाव :** ट्रंप ने पिछले साल आठ मई को ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने का एलान किया था। इसके बाद उसके तेल निर्यात को रोकने के साथ ही उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। ट्रंप ने ईरान पर यह कार्रवाई उसके परमाणु कार्यक्रम और आतंकी गतिविधियों को लेकर की थी।

#### ईरान को बहुत भारी पड़ेगी गलती : डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने सोमवार को कहा, 'हम आने वाले समय में देखेंगे कि ईरान के साथ क्या होता है? अगर उन्होंने कोई हरकत की तो यह बहुत बड़ी गलती होगी और उन पर भारी पड़ेगी।'

कतर में हवाई अड्डे पर खड़ा अमेरिकी लड़ाकू विमान। एपी

## रियाद के समीप तेल पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन से हमला

- ईरान समर्थित आतंकी संगठन हाउती ने ली हमले की जिम्मेदारी
- सऊदी अरब ने अस्थायी रूप से क्रूड की पंपिंग रोकी
- ऊर्जा मंत्री ने कहा, पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात बाधित नहीं

**रियाद, रायटर/प्रेट्र :** सऊदी अरब ने कहा है कि रियाद क्षेत्र में उसके तेल पंपिंग स्टेशन पर विस्फोटक लदे ड्रोन से हमला किया गया है। यमन में सक्रिय ईरान समर्थित आतंकी संगठन हाउती ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यह आतंकी कार्रवाई संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के जलक्षेत्र में सऊदी अरब के दो तेल ट्रैंकरों को निशाना बनाए जाने के दो दिनों बाद मंगलवार को की गई है। सऊदी अरब ने सतर्कता बरतते हुए एक बड़े पाइपलाइन से क्रूड आयल पंपिंग रोक देने की जानकारी दी है।

दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश के ऊर्जा मंत्री खालिद अल-फालिह ने कहा कि दो तेल पंपिंग स्टेशनों पर हमले से तेल उत्पादन या क्रूड और पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि हाल के हमलों ने वैश्विक तेल आपूर्ति पर खतरा पैदा कर दिया है। इसने इस तरह की बाधा पैदा करने वाली गतिविधि के पीछे काम करने वाले आतंकी समूहों का मुकाबला करने की जरूरत को भी साबित कर दिया है। ऐसे आतंकी समूहों में यमन में सक्रिय ईरान समर्थित हाउती आतंकी भी शामिल हैं।

हाउती संचालित मासिराह टीवी ने मंगलवार को सैनिक अधिकारी के हवाले से कहा कि उसने महत्वपूर्ण सऊदी प्रतिष्ठानों पर ड्रोन से हमला किया है। सऊदी के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन यमन में चार साल से हाउती के साथ संघर्ष कर रहा है।

मंगलवार को हुआ हमला और रविवार को यूएई के तट पर वाणिज्यिक पोतों को निशाना बनाने की घटना के बाद खाड़ी देशों में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है। यूएई ने फुजैरा में हुए हमले की प्रकृति का ब्योरा नहीं दिया है। उसने किसी पक्ष या देश पर आरोप भी नहीं लगाया है। रविवार को हुई तोड़फोड़ की घटना में ईरान प्रमुख संदिग्ध है। लेकिन वाशिंगटन के पास इसका कोई ठोस सुबूत नहीं है। तेहरान ने इस घटना में संलिप्तता से साफ इन्कार किया है और वाणिज्यिक पोतों पर हुए हमले को चिंताजनक करार देते हुए इसकी जांच की मांग की है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पश्चिम एशिया में जैसे हालात बनते जा रहे हैं वह इस क्षेत्र के लिए बेहद खतरनाक हैं। एक और ईरान और अमेरिका के बीच ताजा संकट बेहद नाजुक दौर में पहुंच गया है और दूसरी ओर सऊदी अरब से जुड़े ताजा मामले ने इस तनाव को और अधिक बढ़ाने का काम किया है। मौजूदा स्थिति यह है कि कुछ भी हो सकता है। पश्चिम एशिया के इस संकट पर भारत और चीन की भी निगाहें लगी हुई हैं।

#### अमेरिका ने ईरान पर टैंकरों पर हमले का आरोप लगाया

**वाशिंगटन, आइएएनएस :** प्रारंभिक अमेरिकी आकलन ने संकेत दिया है कि सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों और दो अन्य पोतों को हुए नुकसान के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। यह आकलन अंतिम निष्कर्ष नहीं है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका की कई चेतावनियों के बाद हुई घटना के लिए तेहरान जिम्मेवार हो सकता है।

बोस्टन में अदालत में पेश होने पहुंचीं अमेरिकी अभिनेत्री फेलिसिटी हफमैन।

## कॉलेज दाखिला स्कैंडल में अमेरिकी अभिनेत्री हफमैन ने गुनाह कुबूला

**न्यूयॉर्क, एएफपी :** अमेरिकी अभिनेत्री फेलिसिटी हफमैन ने नामी यूनिवर्सिटी में बेटी के दाखिले के लिए रिश्वत देने के मामले में अपना गुनाह मान लिया है। डेसपेरेट हाउसवाइव्स टीवी सीरियल से चर्चित हुईं हफमैन ने सोमवार को अपना गुनाह स्वीकार लिया। मैसाच्युसेट्स के अटॉर्नी एंड्रयू लेलिंग ने इसकी पुष्टि की है। जेल की सजा और भारी जुर्माने से बचने के लिए हफमैन सहित अब तक इस मामले से जुड़े दस आरोपित कोर्ट के समक्ष अपना गुनाह कुबूल चुके हैं।

विभिन्न अमेरिकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाले एसएटी कॉलेज एंट्रेंस एक्जाम में अच्छे स्कोर के लिए रिश्वत देने से जुड़े इस मामले में 50 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें कई हाईप्रोफाइल चेहरे शामिल हैं। हफमैन ने भी अपनी बेटी के दाखिले के लिए 15 हजार डॉलर (करीब 10.5 लाख रुपये) की रिश्वत दी थी। इस मामले में अभिनेत्री को 20 साल तक की सजा के अलावा ढाई लाख डॉलर का जुर्माना भी हो सकता है। रिश्वत कांड के मास्टरमाइंड विलियम रिक सिंगर ने इस स्कैंडल के जरिये ढाई करोड़ डॉलर (करीब 175 करोड़ रुपये) की रकम जुटाई थी। वह भी अपना दोष स्वीकार कर चुका है। मामले में सजा का एलान 13 सितंबर को किया जाएगा।

## अवैध पाकिस्तानियों को वापस भेजेगा अमेरिका

**इस्लामाबाद, प्रेट्र :** अमेरिका 70 से अधिक अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजेगा। एक विशेष चार्टर्ड विमान इनको लेकर बुधवार को पाकिस्तान आएगा। यह जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को दी। नेशनल असेंबली की विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को जानकारी देते हुए कुरैशी ने कहा कि इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया था और उन पर आव्रजन उल्लंघन, आपराधिक आचारण सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

जियो न्यूज ने कुरैशी के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने अमेरिका से उसके नागरिकों को वापस भेजे जाने से पहले कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने को कहा है। कुरैशी ने उन खबरों को खारिज किया, जिसमें अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर वीजा प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। हालांकि उन्होंने यह बात जरूर स्वीकार की ट्रंप प्रशासन ने तीन पाकिस्तानी अफसरों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका ने किन्हीं कारणों के चलते इन तीन अधिकारियों के यात्रा वीजा पर प्रतिबंध लगाया है। जिन अफसरों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और डीजी पासपोर्ट शामिल हैं। कुरैशी ने कहा कि यह प्रतिबंध वास्तव में पाकिस्तान पर नहीं लगाया गया है और इस संबंध में दोनों देशों द्वारा स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। कुरैशी ने कहा कि विदेश मंत्रालय केवल उसी तरह के वीजा जारी करेगा, जिस तरह के अमेरिका करता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका पांच साल के लिए वीजा जारी करता है तो पाकिस्तान भी पांच साल के लिए ही वीजा जारी करेगा।

#### अमेरिका ने चीन-पाक की कंपनियों को 'एन्टिटी सूची' में डाला

**वाशिंगटन, प्रेट्र :** अमेरिका ने पाकिस्तान की एक और चीन की कई कंपनियों समेत 12 विदेशी कंपनियों को अपनी 'एन्टिटी' सूची में शामिल किया है। इन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूची में शामिल किया गया है कि संवेदनशील प्रौद्योगिकी उन लोगों के हाथों में नहीं पड़े जो देश के राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका ने चीन और हांगकांग स्थित चार कंपनियों, दो अन्य चीनी कंपनियों, एक पाकिस्तानी कंपनी और संयुक्त अरब अमीरात के पांच लोगों को इस सूची में शामिल किया है। वाणिज्य मंत्री विल्बुर रोस ने कहा, 'ट्रंप प्रशासन अमेरिकी नागरिकों या राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकने वाले हर कदम के खिलाफ देश की रक्षा करेगा। हम दुनियाभर के लोगों और संगठनों को नोटिस दे रहे हैं कि यदि वे जनसंहार करने वाले हथियारों संबंधी ईरान की गतिविधियों और अन्य अवैध योजनाओं को समर्थन देते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।'

वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो (बीआइएस) द्वारा 'एन्टिटी सूची' को अपडेट करने के बाद रोस ने कहा, 'इसके अलावा, हम चीन की असैन्य-सैन्य एकीकरण नीति को प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की साजिशों के जरिये अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।' गौरतलब है कि बीआइएस ऐसी विदेशी कंपनियों, संगठनों या व्यक्ति को अपनी 'एन्टिटी सूची' में शामिल करता है जो उसके अनुसार अमेरिका की सुरक्षा और विदेश नीति के हितों के विरुद्ध काम करती हैं।

## सौतेली बेटी की हत्या में भारतवंशी महिला दोषी करार

**न्यूयॉर्क, प्रेट्र :** अमेरिका में भारतीय मूल की महिला शमदई अर्जुन (55) को अपनी नौ साल की सौतेली बेटी की हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया गया है। शमदई को तीन जून को सजा सुनाई जाएगी। उसे 25 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

न्यूयॉर्क के क्वींस में रहने वाली शमदई को अदालत ने बीते शुक्रवार को दोषी करार दिया। उसने 2016 में सौतेली बेटी अशदीप कौर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। कोर्ट में दिए बयान के अनुसार, एक चश्मदीद ने शमदई को अपने अपार्टमेंट से पूर्व पति रेमंड नारायण और अपने दो पोतों के साथ बाहर निकलते देखा। बेटी के बारे में पूछने पर उसने कहा कि वह बाथरूम में है। बाथरूम की लाइट कई घंटों से जलती देख इस चश्मदीद समेत पड़ोसियों ने लड़की के पिता सुखजिंदर सिंह को फोन किया। बाथरूम का दरवाजा तोड़ने पर लड़की बाथटब में मृत पाई गई। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। क्वींस के असिस्टेंट अटार्नी माइकल कर्टिस के अनुसार, शमदई ने कई बार लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी।

## पाकिस्तान में दबाई जा रही हैं सीपीईसी के खिलाफ उठने वाली आवाजें

- ओबामा प्रशासन की पूर्व अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों को दी जानकारी
- कहा, पाकिस्तान में अपने हिसाब से नियमों को बदलवा रहा है चीन
- परियोजना के खिलाफ मीडिया भी सवाल उठाने से डरती है

**वाशिंगटन, प्रेट्र :** पाकिस्तान में अरबों डॉलर के चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर (सीपीईसी) के विरोध में आवाजें उठने लगी हैं। लेकिन इन आवाजों को दबा दिया जा रहा है। चीन की इस महत्वाकांक्षी योजना की आलोचना करने को राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी ठहराया जा रहा है। ओबामा प्रशासन की एक पूर्व अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों को यह बात बताई।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ने वाली 60 अरब डॉलर की लागत वाली सीपीईसी, 'बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरआइ) की अहम परियोजना है। 2013 में सत्ता में आने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य दक्षिणपूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप के साथ जमीनी और समुद्री मार्गों का नेटवर्क खड़ा करना है।

जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर अडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज की शमीला चौधरी ने पिछले हफ्ते संसदीय समिति को बताया कि स्थानीय स्तर पर जो लोग सीपीईसी की आलोचना करते हैं, उन्हें अक्सर आतंकवादी करार दे दिया जाता है। चौधरी ने कहा, 'पाकिस्तानी मीडिया में आपको शायद ही कोई ऐसा लेख दिखेगा जिसमें सीपीईसी की आलोचना की गई हो। ऐसा बहुत दुर्लभ है। मीडिया में सीपीईसी के पक्ष में ही खबरें मिलती हैं। विरोध करने वालों को धमकाया जाता है।'

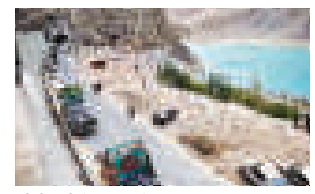

सीपीईसी के तहत हो रहा काम। फाइल

### पाकिस्तान में धन कमाने गया है चीन

चीन के विकास मॉडल के संबंध में सांसदों के प्रश्नों के उत्तर में चौधरी ने कहा कि अमेरिका के सॉफ्ट पावर के बिल्कुल उलट चीन का विकास मॉडल लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान में धन कमाने के लिए है। उन्होंने आगे बताया, 'वे (चीनी) एनक्लेव्ज में रहते हैं और लोग इसे चीनी कॉलोनी भी कहते हैं। ये लोग अपने रेस्त्रां में ही खाने जाते हैं। स्थानीय लोग इससे काफी चिंतित हैं।'

### अमेरिकी हितों को नुकसान

उन्होंने कहा कि सीपीईसी परियोजना भारत-पाकिस्तान के बीच संबंधों को बिगाड़कर अमेरिका के क्षेत्रीय हितों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा, 'चीन का निगरानी का प्रावधान, डेटा कलेक्शन की क्षमता और पाकिस्तानी सेना को नए सामान देने से- ऐसा लगता है कि इससे सुरक्षा स्थिति सुधर सकती है लेकिन ऐसी चीजें निजता के उल्लंघन, सूचना के दुरुपयोग और डेटा के गलत इस्तेमाल के खतरे को भी बढ़ा देती हैं।'

### चीन के चलते मजबूत हुई पाकिस्तानी सेना

चौधरी ने कहा कि चीन की मदद से पाकिस्तान सेना पहले से काफी मजबूत हुई है। पाकिस्तान में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और वह अपने हिसाब से नियमों को भी बदलवा रहा है। जैसे, पाकिस्तान ने चीन से लोन किन शर्तों पर लिया है, यह जनता को नहीं बताया गया है।

## इफ्तार पार्टी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ह्वाइट हाउस में इफ्तार दावत की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को साथ लाता है रमजान का पवित्र महीना...

## ट्रंप ने न्यूजीलैंड और श्रीलंका में आतंकी हमलों पर जताया दुख

**वाशिंगटन, प्रेट्र :** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ह्वाइट हाउस में इफ्तार दावत की मेजबानी की। उन्होंने कहा, 'अमेरिका और दुनियाभर में रहने वाले मुस्लिमों के लिए रमजान पवित्र महीना है। रमजान लोगों को साथ लाता है और लोग उम्मीद, सहिष्णुता और शांति की कामना करते हुए एकजुट होते हैं।' इस मौके पर ट्रंप ने न्यूजीलैंड और श्रीलंका में आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के प्रति दुख भी जताया। गत 15 मार्च को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर की दो मस्जिदों में हुई गोलीबारी में 50 लोग मारे गए थे, जबकि गत 21 अप्रैल को श्रीलंका के तीन चर्चों और तीन लक्जरी होटलों में हुए आत्मघाती धमाकों में करीब 260 लोगों ने जान गंवाई थी।

ट्रंप ने यह इफ्तार दावत अपने प्रशासन के प्रमुख मुस्लिम सदस्यों और विभिन्न देशों के शीर्ष राजनयिकों के लिए दी थी। ट्रंप ने कहा, 'रमजान धर्मार्थ और साथी नागरिकों की सेवा का वक्त होता है। रमजान बेहद खास है। यह परिवारों, पड़ोसियों और समुदायों को करीब लाता है। आज की शाम हमारी संवेदनाएं उन धर्मावलंबियों के साथ भी हैं जिन्होंने हाल के कुछ हफ्तों में मुश्किलों का सामना किया। यह बेहद कठिन दौर रहा है। न्यूजीलैंड की मस्जिदों में मारे गए मुस्लिमों के प्रति हमारे दिलों में गहरा दुख है। हम श्रीलंका, कैलिफोर्निया और पीट्सबर्ग में ईसाइयों, यहूदियों और ईश्वर की अन्य संतानों की मौत से भी दुखी हैं।' अमेरिका के राष्ट्रपति हर साल रमजान के दौरान इफ्तार दावत की मेजबानी करते हैं।

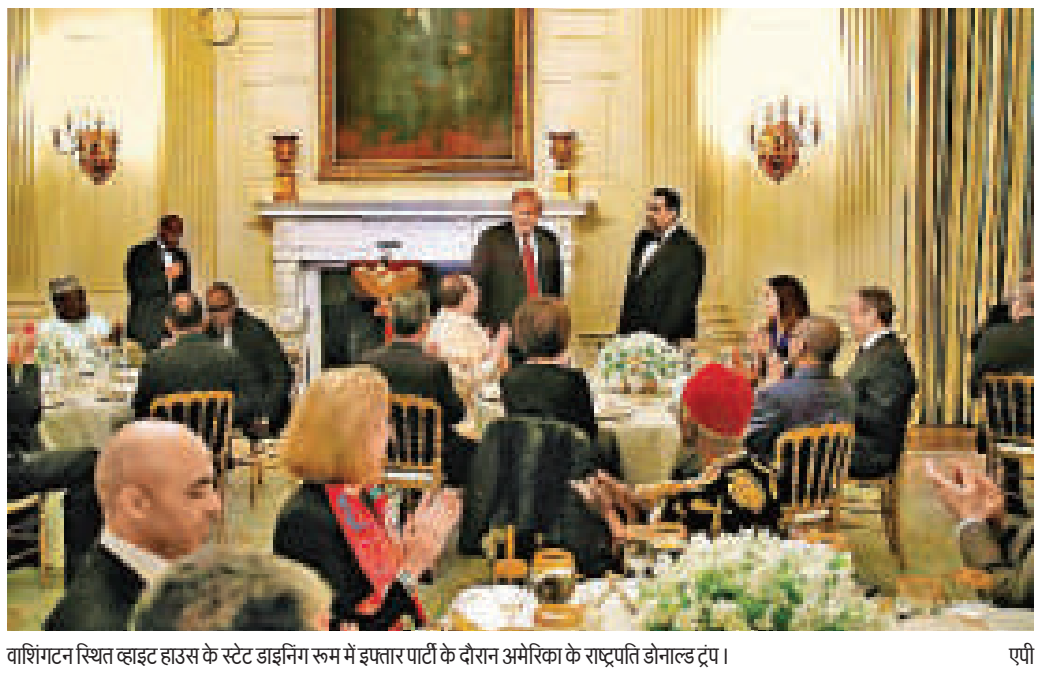

वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम में इफ्तार पार्टी के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एपी